Casual Labourers in the Ministry of Communications

1374. SHRI RAM PUJAN PATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of casual labourers in his Ministry and its offices/departments/subordinate offices/attached offices who have been made regular during the last three years (office-wise and year-wise);

(b) the number of casual workers who have been working for more than two years and have not been made regular and the reasons therefor; and

(c) whether his Ministry has formulated any time-bound programme for making them regular; if so, what are the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI V. N. GADGIL): (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The Ministry follows the general Government orders in the matter.

Offices Housed in rented Buildings

1375. SHRI RAM PUJAN PATEL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the various offices of his Ministry/Subordinate offices/attached offices/Departments are housed in the rented buildings in Delhi and outside Delhi; if so, since when;

(b) the name of each office and the monthly rent of each building occupied along with the date of occupation;

(c) whether it is a fact that his Ministry is not interested to shift these offices from rented buildings to Government buildings; if so, what are the reasons therefor; and

(d) if the answer to part (c) above be in negative what steps have been taken so far to shift these offices from rented buildings to lessen the burden on the exchequer?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI V. N. GADGIL): (a) Yes, Sir.

(b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) No, Sir.

(d) Efforts are being made to shift offices to Government buildings as soon as these become available.

Appointment of 'Ombudsmen'

1376. SHRI NARENDRA SINGH: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Law Commission has in its recent report suggested the appointment of "Ombudsmen" to examine complaints against public authorities and to resolve disputes amicably in order to minimise litigation; and

(b) if so, what were the main recommendations of the Law Commission in this regard and what decision Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): (a) The Law Commission in its 100th Report entitled "Litigation by and against the Government. Some Recommendations for Reform" which was sent to the Government on 8th May, 1984 recommended, *inter-alia* appointment of Litigation Ombudsmen both at the Centre and in the States.

(b) The Report containing all the details and recommendations of the

Commission would be laid before the Parliament after completion of the formalities like translating the same into Hindi and also getting the copies made thereof both in English and in Hindi. The Report is under consideration of the Government.

टेलिफोन विभाग में दुर्विनियोग के संबंध में समाचार

1377. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भोपाल से प्रकाशित 11 जून, 1984 को साप्ताहिक "चरैवैति" में "टेलीफोन विभाग में करोड़ों का गबन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई जांच नहीं की गई है तो क्या सरकार जांच कराने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) यह समाचार 11 से 17 जून, 1984 के "चरैवैति" साप्ताहिक संस्करण में ही जिसका केवल भोपाल से प्रकाशित किया जाता है, मिल सकता है। इंदौर टेलीफोन के टेलीफोन राजस्व विंग में धोखाधड़ी का मामला जानकारी में आया था। इस मामले में विभागीय जांच की गई थी और यह मामला सी०बी०आई० में दर्ज करा दिया गया है।

आकाशवाणी केन्द्रों के समाचार एककों का दर्जा बढ़ाया जाना

1378. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लखनऊ और जयपुर आकाशवाणी केन्द्रों के समाचार एककों का दर्जा बढ़ाया गया है और वहां सम्पादक के पदों का सृजन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार भोपाल आकाशवाणी केंद्र में एक समाचार सम्पादक नियुक्त करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो यह नियुक्ति कब तक हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) नवम्बर, 1982 में आकाशवाणी में जयपुर और लखनऊ में सहायक समाचार सम्पादक का एक-एक पद जिसका वेतनमान 700-1300 रु० था, उन पदों में से था जिनका दर्जा बढ़ाकर 1100-1600 रु० के वेतनमान में समाचार सम्पादक के स्तर का कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभागेतर डाक कर्मचारियों की समस्याओं तथा सेवा शर्तों की जांच हेतु समिति

1379. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभागेतर डाक कर्मचारियों की समस्याओं और सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए संसद-सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का विचार रखती है !

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर ना हो, तो इसके क्या कारण हैं ?